सं0-01/213567/38/6099(/99)/28/2021

प्रेषक

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्यर सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक. 28 मार्च 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में महिला सामर्थ्य योजना अंतर्गत दुग्ध मूल्य श्रृंखला विकास प्रोड्यूसर कंपनी हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदयए

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-4781/2213/एमएसएम/2020-21, दि0.30.12.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 200.00 करोड का बजट प्राविधान किया गया है। योजना शत प्रतिशत राज्य् पोषित योजना है। उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला सामर्थ्य योजना अंतर्गत एन0डी0डी0बी0 डेयरी सर्विसेज के सहयोग से मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी हेतु निम्न् 02 परियोजनाओं के लिये 25 प्रतिशत धनराशि निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्गत किये जाने का अनुरोध मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया गया है:-

क्र0 स0	जनपद का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	कुल लाभान्वित होने वाले परिवार	कुल बजट	25 प्रतिशत धनराशि (करोड में)
1	गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज एवं कुशीनगर	500	20000	34.44	8.61
2	रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ, अयोध्या, कानपुर नगर, फतेहपुर एवं अमेठी	1500	75000	62.29	15.57
योग					24.18

वित्त विभाग द्वारा उक्त् 02 परियोजनाओं हेतु कतिपय शर्तो के अधीन अनुदान सं0-13 के लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-05-महिला सामर्थ्य- योजना-42-अन्य व्यय में प्रावधानित व उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) निर्गत किये जाने पर सहमति प्रदान की गई है।

2. अतएव वित्तीय वर्ष 2021.22 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में से उक्त 02 परियोजनाओं हेतु रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

1. आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक,राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3. धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

4. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

5. स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/ व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

9. धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या.3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12. यूपीएसआरएलएम की झाँसी की बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डेयरी सर्विसेज के साथ संचालित है, उसी तर्ज पर अन्य उत्पादों के लिए भी प्रोड्यूसर कम्पनी स्थापित करते हुए कार्य किया जायेगा। यह टिप्पणी मुख्यतः मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी के उदाहरण पर आधारित है, परन्तु इसी तरह का कार्य किसी भी उत्पाद के लिए किया जाना है।

13. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा बनाये जा रहे प्रोडक्ट के लिए वैल्यू श्रृंखला के विकास में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के साथ कन्वर्जन किया जायेगा।

14. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज(NDS) जो की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड(NDDB) की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली आनुषंगिक संस्था है, को दीनदयाल अन्त्योदय योजना डे-एनआरएलएम सपोर्ट संगठन (DNSO) के रूप में चिन्हित किया है। इसी क्रम में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में केवल महिला सदस्यों के स्वामित्व वाली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनिया स्थापित करने में सहायता कर रही हैं।

15. महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां एवं महिलाओं द्वारा तैयार किये जा रहे अन्य उत्पादों के लिए प्रोड्यूसर कंपनियां गठित कर कार्यवाही कराना, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS) के साथ महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी गठित करने के लिए अनुबंध करना एवं इस योजना के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी।

16. परियोजना के लिए संभावित घटक.वार व्यय का उल्लेख परियोजना दस्तावेज में किया जायेगा। वित्त पोषण के लिए डेयरी वैल्यू श्रृंखला विकास परियोजनाओं के तहत परिकल्पित प्रमुख लागत घटक है। मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को वित्तीय सहायता अधिकतम 03 वर्षों की अवधि के लिये होगी।

17. आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना के तहत वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित गतिविधियों को अन्य स्रोतों/कार्यक्रमों के माध्यम से वित्त पोषित न किया जाए। परियोजना शासनादेश संख्या.467/38-6-21-467एलसी/2021 दिनांक 29.10.2021 के अनुपालन के अनुसार होगा।

18. दिशानिर्देश (Guidelines) के अनुसार मानव संसाधन और प्रशासनिक लागत प्रोड्यूसर कंपनी को कुल वित्तपोषण सहायता के 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

19. परियोजना का वित्तीय लेखा परीक्षा एसआरएलएम के चार्टेड एकाउंटेंट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। ऑडिट रिपोर्ट लेखा परीक्षक की टिप्पणियों और परियोजना के तहत भौतिक प्रगति पर की गई कार्यवाही के साथ राज्यांश शेयर की तीसरी किस्त जारी करने के समय प्रस्तुत की जायेगी।

20. स्वीकृत परियोजना की निगरानी और आवधिक समीक्षा के लिए यू0पी0 एसआरएलएम राज्य स्तर पर एक समिति का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता मिशन निदेशक, यू0पी0 एसआरएलएम करेंगे। राज्य समिति में संयुक्त मिशन निदेशक, राज्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परियोजना प्रबन्धक, वित्त, राज्य परियोजना प्रबन्धक, आजीविका एवं एन0डी0एस0 के सदस्य होंगे। एमओआरडी के प्रतिनिधियों को त्रैमासिक समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।

21. उक्त के अतिरिक्त प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तो के समावेश की जिम्मेदारी आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की होगी।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-05-महिला सामर्थ्य योजना-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (व्यय -नियत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-3445/दस-2021-22 दि0-25.03.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्यर सचिव।

संख्या -01/213567(1)/38-6-22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. निदेशक, कोषागार/ मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
6. अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्यय) अनुभाग -1/2
8. ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरी राम
संयुक्ते सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं0-01/213567/38-6099(99)/28/2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक- 28 मार्च, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में महिला सामर्थ्य योजना अंतर्गत दुग्ध मूल्य श्रृंखला विकास प्रोड्यूसर कंपनी हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-4781/2213/एमएसएम/2020-21, दि0-30-12-2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में रू0 200.00 करोड का बजट प्राविधान किया गया है। योजना शत प्रतिशत राज्य पोषित योजना है। उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला सामर्थ्य योजना अंतर्गत एन0डी0डी0बी0 डेयरी सर्विसेज के सहयोग से मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी हेतु निम्न 02 परियोजनाओं के लिये 25 प्रतिशत धनराशि निम्नांकित विवरण के अनुसार निर्गत किये जाने का अनुरोध मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया गया है :-

क्र0 स0	जनपद का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	कुल लाभान्वित होने वाले परिवार	कुल बजट	25 प्रतिशत धनराशि (करोड में)
1	गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज एवं कुशीनगर	500	20000	34.44	8.61
2	रायबरेली, सुल्तानपुर प्रतापगढ, अयोध्या, कानपुर नगर, फतेहपुर एवं अमेठी	1500	75000	62.29	15.57
योग					24.18

वित्त विभाग द्वारा उक्त 02 परियोजनाओं हेतु कतिपय शर्तो के अधीन अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-05- महिला सामर्थ्य योजना-42-अन्य व्यय में प्रावधानित व उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष **रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र)** निर्गत किये जाने पर सहमति प्रदान की गई है।

2- अतएव वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में से उक्त 02 परियोजनाओं हेतु रू0. **100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र)** को अवमुक्त कर आयुक्त,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

1. आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक,राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3. धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

4. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

5. स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

9. धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

10. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/ अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

12. यूपीएसआरएलएम की झाँसी की बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डेयरी सर्विसेज के साथ संचालित है, उसी तर्ज पर अन्य उत्पादों के लिए भी प्रोड्यूसर कम्पनीज स्थापित करते हुए कार्य किया जायेगा। यह टिप्पणी मुख्यतः मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी के उदाहरण पर आधारित है, परन्तु इसी तरह का कार्य किसी भी उत्पाद के लिए किया जाना है।

13. उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा बनाये जा रहे प्रोडक्ट के लिए वैल्यू श्रृंखला के विकास में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के साथ कन्वर्जन किया जायेगा।

14. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज(NDS) जो की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड(NDDB) की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली आनुषंगिक संस्था है, को दीनदयाल अन्त्योदय योजना डे-एनआरएलएम सपोर्ट संगठन (DNSO) के रूप में चिन्हित किया है। इसी क्रम में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में केवल महिला सदस्यों के स्वामित्व वाली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनिया स्थापित करने में सहायता कर रही हैं।

15. महिला सामर्थ्य योजना' के अंतर्गत मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां एवं महिलाओं द्वारा तैयार किये जा रहे अन्य उत्पादों के लिए प्रोड्यूसर कंपनियां गठित कर कार्यवाही कराना, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS) के साथ महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी गठित करने के लिए अनुबंध करना एवं इस योजना के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी।

16. परियोजना के लिए संभावित घटक-वार व्यय का उल्लेख परियोजना दस्तावेज में किया जायेगा। वित्त पोषण के लिए डेयरी वैल्यू श्रृंखला विकास परियोजनाओं के तहत परिकल्पित प्रमुख लागत घटक है। मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को वित्तीय सहायता अधिकतम 03 वर्षों की अवधि के लिये होगी।

17. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना के तहत वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित गतिविधियों को अन्य स्रोतों/कार्यक्रमों के माध्यम से वित्त पोषित न किया जाए। परियोजना शासनादेश संख्या-467/38-6-21-467एलसी/2021 दिनांक 29-10-2021 के अनुपालन के अनुसार होगा।

18. दिशानिर्देश (Guidelines) के अनुसार, मानव संसाधन और प्रशासनिक लागत प्रोड्यूसर कंपनी को कुल वित्तपोषण सहायता के 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

19. परियोजना का वित्तीय लेखा परीक्षा एसआरएलएम के चार्टेड एकाउंटेंट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। ऑडिट रिपोर्ट लेखा परीक्षक की टिप्पणियों और परियोजना के तहत भौतिक प्रगति पर की गई कार्रवाई के साथ राज्यांश शेयर की तीसरी किस्त जारी करने के समय प्रस्तुत की जायेगी।

20. स्वीकृत परियोजना की निगरानी और आवधिक समीक्षा के लिए यू0पी0 एसआरएलएम राज्य स्तर पर एक समिति का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता मिशन निदेशक, यू0पी0 एसआरएलएम करेंगे। राज्य समिति में संयुक्त मिशन निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक, वित्त, राज्य परियोजना प्रबन्धक, आजीविका एवं एन0डी0एस0 के सदस्य होंगे। एमओआरडी के प्रतिनिधियों को त्रैमासिक समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।

21. उक्त के अतिरिक्त प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तो के समावेश की जिम्मेदारी आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की होगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-05- महिला सामर्थ्य योजना-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-3445//दस-2021-22 दि0-25-03-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 01/213567(1)/38-6-22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
6- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
हरी राम
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।